

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
उत्तराखण्ड,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 25 अक्टूबर, 2016

विषय— श्री अवतार सिंह रावत, उत्तराखण्ड राज्य सरकार के विधिक सलाहकार, को अनुमन्य फीस तथा पद के कर्तव्य/दायित्वों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-516/XXI/2016 दिनांक, 11.07.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्री अवतार सिंह रावत, वरिष्ठ अधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अग्रेत्तर आदेशों तक राज्य सरकार का विधिक सलाहकार नियुक्त कर कैबिनेट मंत्री स्तर (दर्जा) प्रदान किया गया है। उक्त पद के कर्तव्य एवं दायित्वों तथा अनुमन्य फीस का निर्धारण निम्नानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1) शासन के हितों को प्रभावित करने वाले किसी मामले में या किसी विषय पर राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा करने पर परामर्श दिया जायेगा।
- 2) महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड से किसी विषय पर राज्य सरकार द्वारा परामर्श लेने के मामलों में विधिक सलाहकार से भी परामर्श लिया जायेगा।
- 3) विधिक सलाहकार द्वारा मा0 न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, परिषदों में राज्य सरकार का पक्ष रखा जायेगा।

2- विधिक सलाहकार को निम्नानुसार पारिश्रमिक अनुमन्य होगा:-

1	रिटनर फीस नियत	₹ 50,000/- (₹ पचास हजार मात्र) प्रति माह
2	पुस्तकालय भत्ता	₹ 2,500/- (₹ दो हजार पांच सौ मात्र) प्रति माह
3	राज्य के सभी न्यायालयों, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल एवं न्यायाधिकरणों तथा परिषदों आदि में बहस करने हेतु अनुमन्य फीस (चाहे एक से अधिक कितने मामलों में बहस की जाये)	₹ 25,000/- (₹ पच्चीस हजार मात्र) प्रति कार्य दिवस
4	प्रदेश के बाहर (मा0 उच्चतम न्यायालय को छोड़कर) समस्त न्यायालयों, न्यायाधिकरणों एवं परिषदों आदि में राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनुमन्य फीस (चाहे एक से अधिक कितने मामलों में बहस की जाये)	₹ 25,000/- (₹ पच्चीस हजार मात्र) प्रति कार्यदिवस